SAMVARDHINI
PEER REVIEWED MULTILINGUAL E-RESEARCH JOURNAL
(ISSN ONLINE: - 2583-7176)
https://samvardhini.in
https://www.samskritpromotion.in

SAMVARDHINI :- 01/12/2025
Volume - 7
Issue - 2
(ISSN ONLINE :- 2583-7176)
https://samvardhini.in

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 मानववैज्ञानिक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण

केशव पारीक

केशव पारीक
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (प्राकृतिक विज्ञान),
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

शोधसार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy 2020) स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसे लगभग 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लागू किया गया है। यह नीति भारतीय शिक्षा-व्यवस्था को 21वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करने का एक व्यापक प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, समानतापूर्ण, लचीला, बहु-अन्तः-विषयक, बहुभाषायी कौशल-आधारित और रोजगारोन्मुख बनाना है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख प्रावधानों का गहन विश्लेषण करना तथा यह मूल्यांकन करना है कि यह नीति भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक असमानताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, डिजिटल विभाजन और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को किस सीमा तक संबोधित करती है। मानव विज्ञान किसी भी शोध को वस्तुनिष्ठ रूप में करने के लिए अपेक्षित है ना कि व्यक्तिनिष्ठ तौर पर करता है इसी आधार पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का वस्तुनिष्ठ शोध प्रदान कर सके तथा इस दृष्टिकोण से प्राप्त होने वाले सुधारों को लागू कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफल बनाया जा सके।

कूटशब्द - शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा व्यवस्था

प्रस्तावना `

मानव विज्ञान, मानव का अध्ययन है जो मानव के द्वारा किए गए सभी क्रियाकलापों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से संपन्न करता है तथा इस अध्ययन से प्राप्त सुझावों को मानव के लिए और श्रेष्ठ कैसे किया जा सकता है इस पर प्रकाश डालता है, मानव विज्ञान में शोध का बहुत ही गंभीर महत्व है, यह शोध कहीं ना कहीं मानव जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालता है। इस प्रकार के अध्ययन, राष्ट्रीय नीति या योजनाओं को लागू करने, उनमें सुधार करने तथा उनमें उचित परिवर्तन करने इत्यादि कार्यों में अपना योगदान प्रदान करते हैं।

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। यह न केवल ज्ञान के संचार का माध्यम है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, चेतना-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत जैसे विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सामाजिक रूप से विविध देश में शिक्षा नीति का स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह नीति समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की क्षमता रखती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने शिक्षा व्यवस्था को दिशा प्रदान की है। किंतु 21वीं सदी में वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और बदलते श्रम बाजार की आवश्यकताओं के संदर्भ में यह स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अब पर्याप्त नहीं रही है। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को प्रणाली से बाहर निकालकर आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों और जीवन-कौशल के विकास पर बल देती है। यह नीति शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन न मानकर समग्र मानव विकास का माध्यम मानती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-

1. भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर NEP 2020 के प्रभावों का विश्लेषण करना।
2. नीति और उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच के अंतर को समझना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पढ़ने वाले प्रभावों का मानव वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसमें आने वाली चुनौतियों के समाधान को समझना।

अध्ययन-पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। शोध अध्ययन-सामग्री के संकलन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधिकारिक दस्तावेज़, भारत सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स, NCERT के प्रकाशन, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, पुस्तकें तथा UNESCO जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स का उपयोग किया गया है । अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं समालोचनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। उपलब्ध साहित्य के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण कर तार्किक निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। शोध में यह ध्यान रखा गया है की शोध की पद्धतियां मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से संबंधित हों तथा पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हों ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान

1. शिक्षा का संरचनात्मक मॉडल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पारंपरिक 10+2 प्रणाली को समाप्त कर 5+3+3+4 की नई संरचना लागू की है। यह संरचना प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से किशोरावस्था शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग बनाती है। यहाँ बालक को विद्यार्थी के रूप में केन्द्रित रखते हुए उसके समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के साथ अधिगम कैसे हो यह ध्यान रखा गया है।

2. मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा

नीति में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है, जिसे संज्ञानात्मक विकास व सकारात्मक अधिगम के लिए अधिक प्रभावी माना गया है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें हम भाषाविज्ञान को मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण भाग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस महत्व को समझा गया है साथ ही प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है, जो एक लौकिक या परंपरागत महत्व को दृष्टिगत करती है ।

3. बहुविषयक और लचीली शिक्षा

उच्च शिक्षा में विषयों की कठोर सीमाओं को समाप्त कर बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी व्यवस्था छात्रों को लचीलापन प्रदान करती है। मानव शास्त्रीय अध्ययन एक समग्र दृष्टिकोण रखता है, वहीं नई शिक्षा नीति में भी समग्रता पर ध्यान दिया गया है जिससे शिक्षार्थी का मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हो सके।

4. मूल्यांकन सुधार

रटंत प्रणाली पर आधारित परीक्षा प्रणाली के स्थान पर दक्षता और कौशल आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा दिया गया है। यहां भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र मूल्यांकन पर बल डालती है।

साहित्य समीक्षा

विभिन्न विद्वानों और शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार बताया है। कुमार (2021) के अनुसार यह नीति भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करती है। शर्मा (2022) का मत है कि नीति का दृष्टिकोण प्रगतिशील है, किंतु इसका क्रियान्वयन राज्यों में असमान रूप से हो रहा है।

UNESCO (2020) ने डिजिटल शिक्षा को भविष्य की अनिवार्यता बताया है, परंतु भारतीय संदर्भ में डिजिटल विभाजन एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो शिक्षा में असमानता को और गहरा कर सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा की अवधारणा को केंद्र में रखती है। यह नीति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, दिव्यांग विद्यार्थियों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए एक कक्षा को एक सशक्त अधिगम के माध्यम के अवसर इस पर बल देती है, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में उपस्थित विविधता के विभिन्न पहलुओं का एकीकरण कर उनमें समानता का विचार प्रस्तुत करने पर बल देती है। यदि हम सामाजिक समानता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माने तो यहां पर हमें संस्कृति के विविध पहलू के एकीकरण को भी समझना होगा क्योंकि शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं एक कक्षा-कक्ष में विविधता को पोषित करती है । हालाँकि व्यवहारिक स्तर पर ग्रामीण-शहरी अंतर, सरकारी और निजी विद्यालयों की गुणवत्ता में असमानता तथा डिजिटल संसाधनों की कमी नीति के उद्देश्यों को सीमित कर देती है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से नीति की सफलता तभी संभव है जब इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। इस बात की पुष्टि करना की नीतियों के अंतर्गत उपस्थित मूल भावना को किस तरह से निचले स्तर तक लागू करना जरूरी है यदि हम इस प्रयास को और गहन रूप से देखें तो यहां पर विद्यालय, अभिभावक और शिक्षार्थी तीनों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना को समझना काफी आवश्यक हो जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में चुनोतियाँ

शिक्षण संस्थानों में संसाधनों की कमी: भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च स्तर के शिक्षण

संस्थान तथा संस्थान में संसाधनों की कमी लगातार दृष्टिगोचर की गई है यह भी देखा गया है कि शिक्षण संस्थान कहीं ना कहीं अपने मूलभूत ढांचे को प्रस्तुत न करते हुए एक काम चलाउ संस्था के तौर पर देखी जा रही है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में एक बहुत बड़ी रुकावट को इंगित करती है।

शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण: शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों की कमी, शिक्षकों का पठन-पाठन के अलावा अतिरिक्त कार्यों में लगाना, शिक्षा के मूल स्वरूप तथा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रवेश से पारंपरिक शिक्षा में हुए परिवर्तन को शिक्षकों के प्रशिक्षण में अंतर निहित करने का कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं यह व्यवस्था अपर्याप्त सी दिखाई दे रही है| हमें यहां यह ध्यान देना है कि शिक्षकों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी का मित्र बनाएं, जिससे वह अपने शिक्षण कार्य में इन प्रौद्योगिकी तकनीक का समावेशन करके अपने शिक्षण कार्य को रोचक तथा अभिप्रेरणा युक्त बना सके

डिजिटल अवसंरचना का अभाव: यदि हम सरकारी विद्यालयों की बात करें, तो वहां पर संसाधनों की कमी होने के कारण डिजिटल अव संरचना की भी बहुत कमी देखी गई है; जैसे वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से शिक्षा का डिजिटलकरण हुआ है | पारंपरिक रूप से चलने वाले विद्यालयों को एक बहुत बड़े डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता है जिसका अभाव कहीं ना कहीं वर्तमान विद्यार्थियों को शिक्षा व्यवस्था को अरुचिकर बना रहा है।

राज्यों के बीच असमान क्रियान्वयन: शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सीमा विहीन होनी चाहिए जो आज के समय में, जहां हम वैश्वीकरण की बात करते हैं वही भारत में दो राज्यों के बीच यह देखा जाता है की शिक्षा का आदान-प्रदान उस स्तर पर नहीं हो पता जिस स्तर पर यह अपेक्षित है| राज्यों के बीच में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के आसमान क्रियान्वन के कारण विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में गमन करता है। उदाहरणार्थ- मानव शास्त्र भी एक विषय है जो कुछ ही विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है और विद्यालय स्तर पर यह विषय नहीं पढ़ाया जाता इस हेतु विद्यार्थी अगर यह विषय पढ़ना पड़ेगा तो उसे अन्य राज्य में जाकर इस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा | यही आसमान क्रियावन कहीं ना कहीं शिक्षा को बाधित करता है।

नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आई है| भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना को समझते हुए इसमें उपस्थित सभी योजनाओं एवं क्रिया प्रणाली को लागू करते हुए संभावनाओं की नई दिशा शिक्षार्थियों के लिए शीघ्र प्रारम्भ करें तथा कहीं ना कहीं शिक्षा को वैश्वीकरण के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें।

शिक्षा में नवाचार बहुत ही जरूरी है क्योंकि परंपरागत मूल्य में नवाचार को सम्मिलित करके हम हमारे विद्यार्थियों के लिए एक नवीन रोचक शिक्षा प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए रचनात्मक प्रयासों के साथ शिक्षा व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं।

कौशल आधारित शिक्षा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बहुत बल दिया था तथा इसे प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयास भी किया था| आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल आधारित शिक्षा पर बल डालती है। बहुत सारे राज्य विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के द्वारा कौशल आधारित वह रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देते हैं उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार में हाल ही में एक 'नीव' प्रोग्राम प्रारंभ किया है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के उद्यमियों के साथ वार्तालाप करने उनके साथ वर्कशॉप करने तथा स्वयं के द्वारा बनाए गए नवीन उत्पादक या व्यवसाय को किस प्रकार से चलाया जाता है। इन सब व्यवस्थाओं पर बल दिया गया है| इस हेतु दिल्ली सरकार विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान कर रही है तथा कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को समाज से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा और सोचें तो विद्यार्थियों में नौकरियां ढूंढने की बजाय नौकरियां पैदा करने की इच्छा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का आना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को एक रोजगार उन्मुख प्रेरणा प्रदान करता है। इस तरह के प्रोग्राम अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल भावना को पूरी करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि वैश्वीकरण के दौर में भारत देश कहीं ना कहीं निर्यात और आयात के संतुलन में जूझ रहा है आज भारत देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा से किस तरह से मुकाबला किया जाए यह एक यक्ष-प्रश्न है, यहां हम जापान देश का उदाहरण भी ले सकते हैं जो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले को झेलते हुए भी आज विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। जापानी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते हुए यह चीज देखी गई है कि जापान देश शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र पर काफी बल डालता है। उसका मानना है कि आज शिक्षा पर किया गया खर्चा कहीं ना कहीं भविष्य में हमें वैश्विक स्तर पर खड़ा करने में सहायता प्रदान करेगा भारत देश जापान, सिंगापुर तथा फिनलैंड जैसे देशों से यह सीख सकता है कि किस तरह से एक शिक्षा के हथियार से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को जीता जा सकता है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा 2020 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का बहुत ही बड़ा कदम है इसे लागू करने में सभी राज्य सरकारों को भारत सरकार के दृष्टिकोण को समझते हुए अपने राज्य की भौगोलिक सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति

को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने का प्रयास करना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए की इस शिक्षा नीति में अपने राज्य के हिसाब से किए गए परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना का हनन न हो।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानव शास्त्रीय परिपेक्ष से अध्ययन करने पर यह दृष्टिगोचर होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत हद तक वंचित तथा उपेक्षित वर्गों के लिए मुख्य धारा से जुड़ने का एक साधन है। इस साधन का प्रयोग राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और दूरगामी परिवर्तन का प्रयास है। यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, आधुनिक और मानव-केंद्रित बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। हालांकि, नीति की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी, समान और संवेदनशील क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि इसे पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित मानव शक्ति और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाए, तो यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला सकती है।

मानवविज्ञान के दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखने पर हम यह समझते हैं की बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग शिक्षार्थी कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपनी पारंपरिक चीजों को पीछे छोड़ते हैं। इन वर्गों के लिए पारंपरिक सांस्कृतिक परिवेश रोजगार उन्मुख था लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा के कारण यह अपने पारंपरिक रोजगार उन्मुख सांस्कृतिक परिवेश से दूर होते चले गए| कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इन विषयों को भी शैक्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके इन वर्गों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर यहां यह समझना जरूरी है कि पारंपरिक मूल्यों को साथ में लेकर हम नवीन शिक्षा नीति 2020 को सुव्यवस्थित प्रकार से अपनी शिक्षा व्यवस्था में लागू कर सकते हैं। जिससे मुख्य धारा में जुड़ने के साथ ही इन वर्गों को एक हाशिए की मानसिकता का सामना ना करना पड़े। वंचित वर्ग से विद्यार्थी जिस परिवेश से आता है, उसके लिए वह परिवेश उसका परिधान, उसके मूल्य स्वाभाविक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन मूल्यों, प्रथाओं, रीतियों से किनारा करना विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही चुनौती पूर्ण कार्य होता है। इन वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास में हम कहीं इन मूल्यों को पीछे ना छोड़ दें, इस बात का ध्यान रखना ही होगा ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Government of India. (2020). *National Education Policy 2020. Ministry of Education.*

Kumar, A. (2021). *Educational reforms in India. Orient Blackswan.*

Sharma, R. (2022). *National Education Policy 2020: Opportunities and challenges. Shiksha Vimarsh, 15(2), 45–58.*

NCERT. (2021). *Educational reforms in India. National Council of Educational esearch and Training.*

UNESCO. (2020). *Education in a post-COVID world. UNESCO Publishing.*

Spindler, G. D. (Ed.). (2000). *Fifty years of anthropology and education: 1950–2000. Lawrence Erlbaum Associates.*

Levinson, B. A., Foley, D. E., & Holland, D. C. (Eds.). (1996). *The cultural production of the educated person. State University of New York Press.*

Erickson, F. (2011). *Culture and education. Wiley-Blackwell.*